COE संवाद

27 अक्टूबर २०२५

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

ASCI
Agriculture Skill Council of India

CEASI
CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

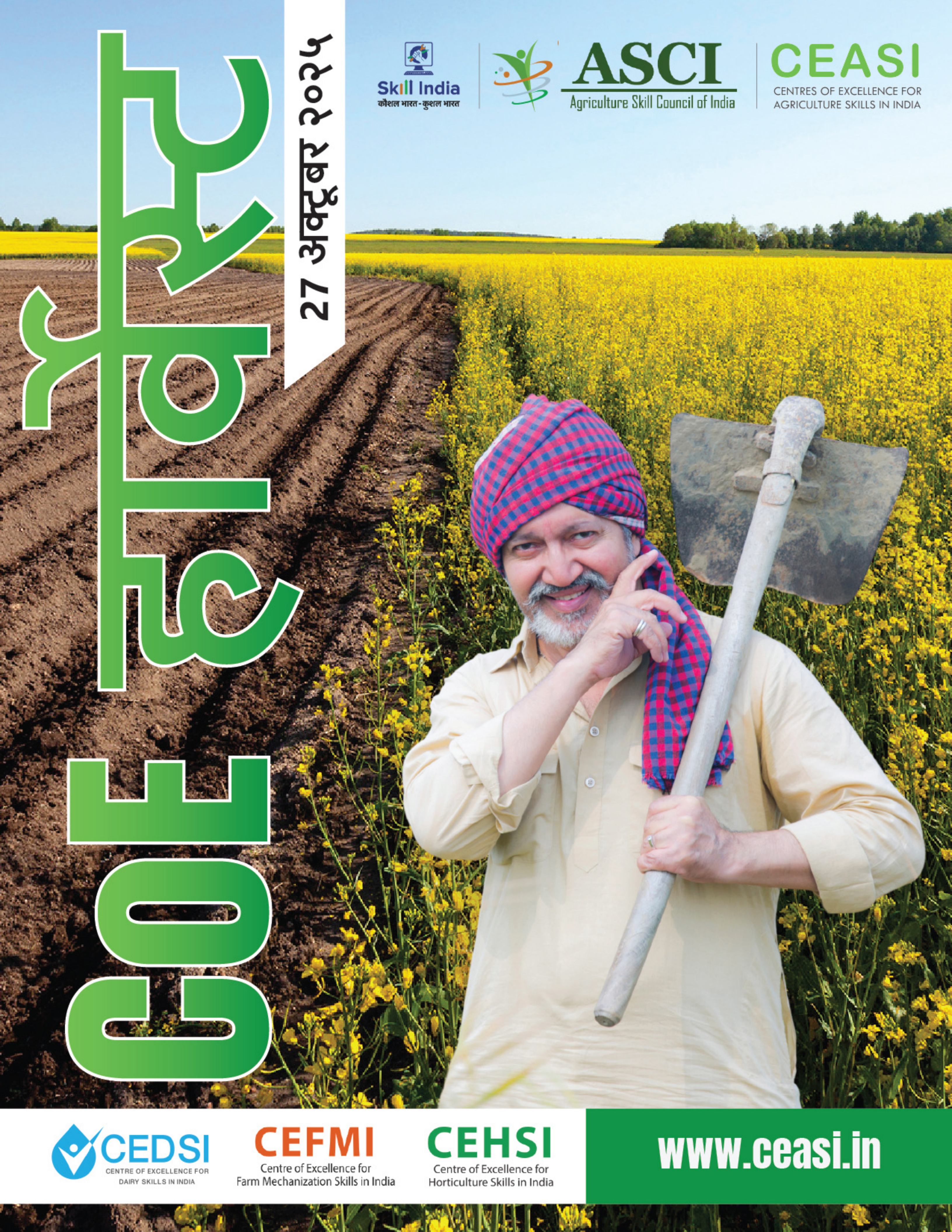

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

प्रिय पाठकों,
हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुँच पाना हमारे लिए एक विशेषाधिकार है। यह समाचार पत्र CEASI की गतिविधियों की धड़कन को दर्शाता है, जो ASCI के संरक्षण में कार्यरत है, और हमारे सामूहिक सफ़र को कौशल विकास एवं सतत कृषि की दिशा में प्रतिबिंबित करता है। यहाँ साझा की जाने वाली हर कहानी हमारी टीमों, साझेदारों और कृषि समुदायों की समर्पित भावना का प्रमाण है। हमारा मिशन स्पष्ट है: किसानों और कृषि-पेशेवरों को वह कौशल, ज्ञान और तकनीक प्रदान करना जिसकी उन्हें बदलते समय में सफल होने के लिए आवश्यकता है। नवाचार और जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मिलाकर, हम एक अधिक उत्पादक, लचीले और समावेशी कृषि क्षेत्र की नींव रख रहे हैं।
मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस समाचार पत्र को पढ़ें, सीखें और इसमें प्रस्तुत अवसरों में सक्रिय रूप से भाग लें। आपकी सहभागिता ही विचारों को प्रभाव में बदलती है।

डॉ. सतेंद्र सिंह आर्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रिय पाठकों,
CEASI का साप्ताहिक समाचार पत्र केवल गतिविधियों का सारांश नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा मंच है, जहाँ विचारों का आदान-प्रदान, उपलब्धियों का उत्सव और भारतीय कृषि तथा इसके सहायक क्षेत्रों जैसे डेयरी, बागवानी, कृषि मशीनीकरण, जलवायु लचीलापन आदि के भविष्य के लिए हमारी साझा दृष्टि को और मजबूत किया जाता है। प्रत्येक अंक कृषि क्षेत्र और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नवाचार, सहयोग और प्रगति की कहानियाँ लेकर आता है।
आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान ज्ञान साझा करने, नवीनतम विकासों को सामने लाने, क्षमता निर्माण करने और सफलता की कहानियाँ हर स्तर पर किसान के खेत से लेकर नीति-निर्माताओं तक पहुँचाने पर रहेगा। ताकि आधुनिक उपकरण, तकनीकें और सर्वोत्तम प्रथाएँ उन तक पहुँच सकें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
मैं स्वीकार करता हूँ कि यह समाचार पत्र अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। मैं पाठकों और हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें प्रस्तुत पहलों, प्रशिक्षणों और अद्यतनों से जुड़े रहें, और ऐसी प्रमुख उपलब्धियों व घटनाओं को साझा करें जिन्हें यहाँ प्रकाशित किया जा सके। इसके दायरे, प्रकाशन की आवृत्ति, नए अनुभाग जोड़ने और सुधार के लिए आपके विचार इसे एक आदर्श पत्रिका बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जो हमें साथ मिलकर और अधिक मजबूत बनने के अवसर प्रदान करेगी।

जसवंत सिंह कालसी
मुख्य परिचालन अधिकारी

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- 15+ राज्य
- 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

कर्नाटक में कृषि यंत्रों पर जीएसटी में बड़ी राहत

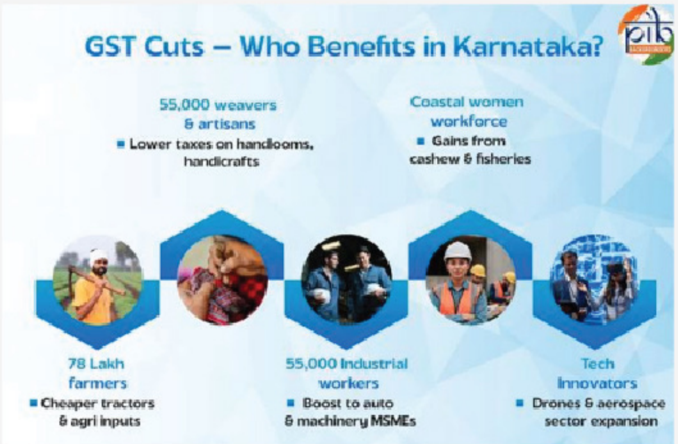

कर्नाटक में कृषि यंत्रीकरण और ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में कमी

कर्नाटक के किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण अब अधिक सुलभ और किफायती होगा। ट्रैक्टर और कृषि मशीनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है, जबकि ट्रैक्टर पार्ट्स पर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खरीद और मरम्मत की लागत कम होगी। छोटे और सीमांत किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा जो भूमि तैयारी, कटाई और फसल-उपरांत कार्यों के लिए मशीनें अपनाने में कठिनाई झेलते हैं। कम कर दरों से किसान, एफपीओ और कस्टम हायरिंग केंद्र उपकरणों में निवेश या किराए पर लेने के लिए उत्साहित होंगे, जिससे श्रम निर्भरता घटेगी और कार्यकुशलता बढ़ेगी। यह सुधार हुबली-धारवाड़, बेलगावी और बेंगलुरु के कृषि मशीनरी उद्योगों के लिए भी फायदेमंद होगा। बढ़ता यंत्रीकरण उत्पादकता, फसल गुणवत्ता और समय पर कार्यों में सुधार लाएगा, जो जलवायु-स्मार्ट खेती के लिए आवश्यक है। कर सुधार ग्रामीण जीवन को सशक्त करेगा और आधुनिक, तकनीक आधारित कृषि को गति देगा।

उड़ीसा ने रबी मौसम के लिए यंत्रीकरण पर फोकस बढ़ाया

उड़ीसा का ध्यान यंत्रीकरण और रबी उत्पादकता पर केंद्रित

उड़ीसा ने आगामी रबी सीजन में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए यंत्रीकरण, समय पर इनपुट आपूर्ति और जलवायु अनुकूल प्रथाओं पर केंद्रित योजना बनाई है। राज्य ने 2026 तक 23.26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए बीज, उर्वरक और फील्ड मार्गदर्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। करीब 29.30 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होगी, जिसमें दालें, तिलहन, सब्जियां और मसाले प्राथमिक फसलें होंगी। भूमि उपयोग को अनुकूल बनाना और सिंचाई कवरेज बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। यंत्रीकरण को फार्म मेकेनाइजेशन प्रोग्राम, पीएम धन धान्य योजना और दाल-तिलहन व बागवानी मिशनों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य बुवाई, फसल संरक्षण, कटाई-पश्चात प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में दक्षता लाना है। पूरक कार्यक्रम जैसे राइस फेलो प्रबंधन, श्री अन्ना अभियान, जलग्रहण विकास और बागवानी मिशन विविधीकरण, स्थिरता और बेहतर किसान आय को समर्थन देंगे।

एफएओ ने सतत व स्मार्ट खेती नवाचारों को दी मान्यता

एफएओ ने सतत और यंत्रीकृत खेती में नवाचार को सराहा रोम में 2025 विश्व खाद्य मंच पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने सतत पौध उत्पादन और संरक्षण में नवाचारों को मान्यता दी। इसमें रोबोटिक्स, स्वचालन और डिजिटल उपकरणों से युक्त स्मार्ट खेती की सराहना की गई, जो कुशल और जलवायु-संवेदनशील खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देती है। कृषि ड्रोन, स्वायत्त फील्ड रोवर, सटीक स्प्रे सिस्टम और डिजिटल मॉनिटरिंग प्लेटफ़ॉर्म फसल प्रबंधन को सरल बना रहे हैं, श्रम घटा रहे हैं और संसाधनों के उपयोग को बेहतर कर रहे हैं। ये बीजारोपण, फसल संरक्षण, सिंचाई और डेटा-आधारित निर्णयों में मदद करते हैं। इनसे रसायनों के सीधे संपर्क में कमी आती है, जिससे कार्यस्थल अधिक सुरक्षित बनता है। विभिन्न देशों के उदाहरणों ने उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने में इन तकनीकों के प्रभाव को दर्शाया। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास हेतु पहलें भी चल रही हैं। एफएओ ने कहा कि ये प्रयास सतत खाद्य प्रणालियों और ग्रामीण विकास को मजबूती देते हैं।

त्रिपुरा में धान खेतों के लिए ड्रोन आधारित कीट नियंत्रण

त्रिपुरा धान खेतों में ड्रोन तकनीक से स्मार्ट कीट प्रबंधन की शुरुआत:

आधुनिक कृषि को सशक्त बनाने के लिए कृषिविज्ञान केंद्र (केवीके) सिपाहीजाला, सीएयू (आई) और कृषि विभाग, त्रिपुरा सरकार ने बिशालगढ़ उपखंड में धान के खेतों में ड्रोन आधारित कीट और रोग प्रबंधन शुरू किया है। 23 अक्टूबर 2025 को चंदन नगर ग्राम पंचायत में हुए प्रदर्शन में करीब 50 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में दिखाया गया कि ड्रोन से लक्षित और समय पर छिड़काव संभव है, जिससे रासायनिक उपयोग घटता है, श्रम बचता है और किसानों का रसायनों से संपर्क कम होता है। यह विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपयोगी है जहां त्वरित कीट नियंत्रण जरूरी है। कार्यक्रम में विधायक सुशांत देब और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पहल के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण, लाइसेंसिंग और जागरूकता भी दी जा रही है। यह गतिविधि सीएयू और आईसीएआर-एटारी क्षेत्र VII के मार्गदर्शन में हुई।

तेलंगाना में जल्द शुरू होगी 'हर द्वार बागवानी' पहल

तेलंगाना में 'हर द्वार बागवानी' शीर्षक से एक नई पहल जल्द शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक घर तक बागवानी फसलों और उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के तहत ताज़ी उपज और मूल्यवर्धित बागवानी उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुँचाकर किसानों और उपभोक्ताओं के बीच मजबूत संबंध स्थापित किए जाएंगे, जिससे पोषण विविधता और शहरी हरियाली को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस पहल के अंतर्गत किसानों को पारंपरिक कृषि से बागवानी की ओर प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जिससे उन्हें आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों की जानकारी दी जा सके। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में लोगों को छत और रसोई बागवानी के माध्यम से आत्मनिर्भरता और सतत जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह पहल राज्य की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत बागवानी को आय सृजन, जलवायु अनुकूलता और खाद्य सुरक्षा का प्रमुख माध्यम बनाया जा रहा है।

सतत खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डच–भारतीय सहयोग का नया चरण शुरू

डच हॉर्टिकल्चर क्लस्टर हॉर्टीरोड टू इंडिया 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत में एक नई मिशन यात्रा शुरू करने जा रहा है, जो सतत और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में डच–भारतीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीन वर्षों के संयुक्त अनुसंधान, डिज़ाइन और पायलट परियोजनाओं के बाद यह साझेदारी अब योजना से कार्यान्वयन के चरण में प्रवेश कर रही है। इस दौरान एक विशेष रूप से तैयार की गई रूपरेखा भारत के बागवानी क्षेत्र को भविष्य के लिए सक्षम और स्थायी खाद्य प्रणाली में बदलने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगी।

यह मिशन नई दिल्ली, बेंगलुरु और पंजाब में आयोजित होगा, जहाँ उच्च-प्रौद्योगिकी ग्रीनहाउस मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा और स्थानीय साझेदारियों को और मजबूत किया जाएगा। यह पहल आधुनिक कृषि तकनीकों को शिक्षा, वित्त और खुदरा नेटवर्क से जोड़कर एक संपूर्ण सतत उत्पादन तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है। वर्ष 2026 तक भारत का पहला पूर्ण रूप से संचालित हाई-टेक ग्रीनहाउस उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है, जो जल और ऊर्जा की बचत के साथ अधिक उपज और वर्षभर सुरक्षित, कीटनाशक-मुक्त एवं पौष्टिक फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

गुजरात में फूलों की खेती तीन गुना बढ़ी, ग्रामीण आय में इज़ाफा

वडोदरा: पिछले दो दशकों में गुजरात में पुष्पोत्पादन (फ्लोरिकल्चर) ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में फूलों की खेती का क्षेत्रफल वर्ष 2024–25 में बढ़कर 21,229 हेक्टेयर हो गया है, जो 1990 के दशक के मध्य में लगभग नगण्य था। राज्य उद्यान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बेहतर बीज गुणवत्ता और उन्नत खेती पद्धतियों के कारण फूल उत्पादन में 4.6 गुना वृद्धि हुई है, जिससे यह क्षेत्र राज्यभर के हजारों किसानों के लिए आय का एक सशक्त माध्यम बन गया है।

दशहरा, दिवाली और गुजराती नववर्ष जैसे त्योहारों के दौरान बढ़ती मांग ने गेंदे, गुलाब और गेलार्डिया जैसे फूलों के बाजार को व्यापक बनाया है। पंचमहल जिले के हलोल तालुका सहित कई गांव अब फूल उत्पादन के प्रमुख केंद्र बन गए हैं, जहाँ छोटे और मध्यम किसान भी लाभदायक और स्थायी बाज़ार की संभावना को देखते हुए पुष्पोत्पादन अपना रहे हैं। यह तेजी से बढ़ता क्षेत्र दर्शाता है कि कृषि में विविधीकरण से ग्रामीण गुजरात में आर्थिक प्रगति और नए रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में हिमाचल ने प्रदर्शित की बागवानी उत्कृष्टता

हिमाचल प्रदेश ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की देश की प्रमुख वैश्विक प्रदर्शनी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस आयोजन में, एपीडा के सहयोग से हिमाचल प्रतिनिधिमंडल ने कई देशों के अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ संवाद स्थापित किया और राज्य के प्रीमियम बागवानी उत्पादों को प्रस्तुत किया। उद्यान विभाग द्वारा लगाए गए विशेष मंडप में सेब, कीवी, पर्सिमन, ड्रैगन फ्रूट, शहद, जूस, लाल चावल और विदेशी सब्जियों जैसी विविध फसलों को प्रदर्शित किया गया, जिससे हिमाचल को उच्च मूल्य वाली बागवानी का केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया।

यह मंडप अपने नवाचार और मूल्यवर्धित उत्पादों के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र बना। स्टार्टअप्स और उद्यमियों ने फलों पर आधारित पेय, विशेष चाय, मधुमक्खी उत्पाद, आवश्यक तेल तथा कॉर्डिसेप्स जैसे उच्च मूल्य वाले मशरूम उत्पादन जैसे नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए। यह भागीदारी हिमाचल की उस दिशा को दर्शाती है जिसमें राज्य नवाचार, मूल्य संवर्धन और निर्यात क्षमता को बढ़ाकर किसानों की आय में सुधार और वैश्विक बाजारों से मजबूत जुड़ाव की ओर अग्रसर है।

धगवार दूध संयंत्र बनेगा हिमाचल का सबसे आधुनिक डेयरी केंद्र

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बन रहा धगवार मिल्क प्लांट राज्य की डेयरी अवसंरचना में बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। ₹225 करोड़ की लागत से विकसित यह संयंत्र प्रतिदिन एक लाख लीटर दूध प्रसंस्करण करने की क्षमता वाला राज्य का सबसे उन्नत केंद्र होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत बन रहे इस संयंत्र का उद्देश्य किसानों को बेहतर दुग्ध-संग्रह, शीतलन और प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह परियोजना स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। संयंत्र चालू होने के बाद इसमें घी, मक्खन, दही और पनीर जैसे उत्पाद बनाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना राज्य को आत्मनिर्भर दुग्ध उत्पादन की दिशा में मजबूत करेगी और तकनीक आधारित डेयरी विकास का उदाहरण बनेगी।

पंजाब में ब्लॉक स्तरीय दुग्ध प्रतियोगिता से डेयरी मानकों को बढ़ावा

पंजाब सरकार ने राज्यभर के 154 ब्लॉकों में ब्लॉक-स्तरीय दुग्ध प्रतियोगिता 2025–26 शुरू की है ताकि डेयरी किसानों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया जा सके।

पशुपालन विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य ऐसे किसानों को सम्मानित करना है जो पशु देखभाल और पोषण के माध्यम से अधिक दूध उत्पादन करते हैं।

हर ब्लॉक में मासिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें गायों और भैंसों की स्वच्छता, उत्पादकता और पोषण प्रबंधन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

विजेताओं को प्रशिक्षण और सम्मान प्रदान किया जाएगा जिससे गुणवत्ता सुधार के प्रति उत्साह बढ़ेगा।

अधिकारियों के अनुसार, यह पहल किसानों की आय बढ़ाने के साथ वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन को बढ़ावा देगी और सहकारी डेयरियों को भी सशक्त बनाएगी।

₹1,166 करोड़ की डेयरी और पशुधन परियोजनाएं ग्रामीण विकास को देंगी गति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹1,166 करोड़ की डेयरी और पशुधन परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। इन परियोजनाओं में यूएचटी दूध, मिल्क पाउडर और चारा उत्पादन संयंत्र शामिल हैं जो कई राज्यों में डेयरी अवसंरचना को आधुनिक बनाएंगे।

इनसे 12 लाख से अधिक किसानों को दुग्ध संग्रह, शीत भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार का लाभ मिलेगा।

यह पहल टिकाऊ डेयरी वैल्यू चेन बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है।

महिला स्व-सहायता समूहों को डेयरी सहकारिताओं में शामिल करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम भारत को वैश्विक डेयरी नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

भारत को शुरू करनी होगी "हरित चारा क्रांति

भारत का डेयरी क्षेत्र, जो विश्व में सबसे बड़ा है, इस समय हरे चारे की गंभीर कमी का सामना कर रहा है जिससे दूध उत्पादन और किसानों की आजीविका पर असर पड़ सकता है।

देश में हरे चारे की 11–32%, सूखे चारे की 23% और सघन चारे की 40% से अधिक कमी दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण बरसीम और मक्का जैसे पारंपरिक चारा फसलों की पैदावार में गिरावट आई है। इस कमी के चलते दूध उत्पादन घट रहा है, पशुओं की प्रसव अवधि बढ़ रही है और पशु-चारा लागत बढ़ने से किसानों की आय प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय चारा मिशन की मांग की है जो उच्च उत्पादन वाली फसलें, सामुदायिक साइलो और चारा बैंक जैसी पहल को बढ़ावा दे। यह कदम भारत की दुग्ध-आधारित ग्रामीण वृद्धि को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है।

गूगल ने भारत में विकसित कृषि एआई उपकरणों का विस्तार एशिया-प्रशांत देशों तक किया

भारत की कृषि नवाचार क्षमता को नया वैश्विक मान्यता मिली है क्योंकि गूगल ने अपने भारत में विकसित एआई उपकरण ALU और AMED को कई एशिया-प्रशांत देशों में विस्तारित किया है।

ये उपकरण किसानों को मौसम पूर्वानुमान, सिंचाई अनुकूलन और फसल रोग पहचान में सहायता प्रदान करते हैं।

यह विस्तार भारत की तकनीक-आधारित कृषि समाधानों में अग्रणी भूमिका को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपकरण लाखों छोटे किसानों को डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगे।

यह पहल भारत के डिजिटल कृषि मिशन से मेल खाती है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है।

यह भारत के लिए तकनीक और कृषि उत्पादकता को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

केंद्रीय कृषि मंत्री का वेल्लोर के आईसीएआर-केवीके दौरा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के आईसीएआर-केवीके वेल्लोर का दौरा कर किसानों और वैज्ञानिकों से संवाद किया। दौरे का मुख्य उद्देश्य पीएम-दक्ष, दलहन उत्पादन और प्राकृतिक खेती जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था। किसानों ने मिट्टी की सेहत, फसल विविधीकरण और मोटे अनाज की खेती से जुड़ी सफल कहानियां साझा कीं।

मंत्री ने केवीके की भूमिका की सराहना की जो शोध को खेतों तक पहुंचाने में अहम रही है, खासकर महिला किसानों के बीच। उन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के सरकार के संकल्प को दोहराया। यह संवाद ग्रामीण नवाचार और किसान सशक्तिकरण के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

केरल में टिकाऊ काजू खेती मॉडल की खोज शुरू

केरल ने टिकाऊ काजू खेती मॉडल खोजने के लिए पायलट शुरू किया केरल प्लांटेशन कॉर्पोरेशन (पीसीके), कासरगोड ने दक्षिण भारत के छोटे किसानों के लिए उत्पादक और जलवायु-सहिष्णु काजू खेती मॉडल खोजने हेतु प्रयोगात्मक परियोजना शुरू की है। यह जून में प्रारंभ हुई, जिसे निदेशालय ऑफ काजू एंड कोको डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषित फ्रंटलाइन टेक्नोलॉजी डेमो कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। परियोजना में तीन रोपण पैटर्न की तुलना की जा रही है—घना रोपण ड्रिप सिंचाई के साथ, सामान्य दूरी सिंचाई सहित, और सामान्य दूरी बिना सिंचाई। एक हेक्टेयर पर धराश्री, सलभा, धन, मदक्कथारा 1 और 2, और प्रियंका जैसी छह उच्च उत्पादक किस्में लगाई गई हैं ताकि पौधों की वृद्धि, कीट सहनशीलता और लाभ का विश्लेषण हो सके। घनी रोपाई में 400 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं, जो उपज दोगुनी कर सकती है। पारंपरिक विधि में लगभग 200 पौधे होते हैं। पीसीके किसानों को अनुकूल मॉडल देना चाहता है ताकि वे अनियमित वर्षा और कीट नुकसान जैसी चुनौतियों से निपट सकें। कई राज्यों के किसान इस परियोजना का दौरा कर रहे हैं, और 40-60 रुपये में तैयार पौधे सीधे इस्टेट से उपलब्ध हैं।

लुधियाना में आयोजित इंटरफेस कार्यशाला में पराली जलाने के स्थायी विकल्पों पर जोर

लुधियाना– धान अवशेष जलाने की समस्या को समाप्त करने के प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पंजाब कृषि विभाग के सहयोग से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में फसल अवशेष प्रबंधन पर इंटरफेस कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकारी, किसान, वैज्ञानिक और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने धान की पराली प्रबंधन के लिए व्यवहारिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान पर चर्चा की। विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य ऐसी सतत पद्धतियों को बढ़ावा देना था जो मृदा स्वास्थ्य को सुधारें, जल संरक्षण में सहायक हों और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करें।

पीएयू और आईसीएआर संस्थानों के विशेषज्ञों ने पराली अपघटन, लागत–लाभ विश्लेषण और क्षेत्र-विशिष्ट तकनीकों पर अपने अनुभव साझा किए। किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन योजनाओं के तहत गुणवत्तापूर्ण मशीनरी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला का समापन अंतर-विभागीय समन्वय, नीतिगत सहयोग और किसान सहभागिता को सशक्त बनाकर शून्य-जलन आधारित कृषि प्रणाली को अपनाने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया एमआईडीएच के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया(CEHSI) द्वारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के तहत 3 दिवसीय फील्ड-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। यह पहल हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी (HSHDA) के सहयोग से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों, ग्रामीण युवाओं और नए उद्यमियों को बागवानी क्षेत्र में व्यावहारिक कौशल और तकनीकी ज्ञान से सशक्त बनाना है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बागवानी से जुड़े कई रोजगार आधारित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे — सब्जी उत्पादक, जैविक उत्पादक, मशरूम उत्पादक, संरक्षित खेती उत्पादक, फसल कटाई के बाद हानि प्रबंधन तकनीशियन, मास्टर गार्डनर, मधुमक्खी पालक, उष्णकटिबंधीय एवं उप-उष्णकटिबंधीय फल उत्पादक और फ्लोरीकल्चरिस्ट (फूल उत्पादक) आदि। प्रत्येक प्रशिक्षण में कक्षा सत्रों के साथ-साथ खेतों पर व्यावहारिक प्रदर्शन भी शामिल है, ताकि प्रतिभागियों को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो सके।

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा के कई जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं — झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकूला। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम आधुनिक खेती की तकनीकों, संसाधनों के कुशल प्रबंधन, फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और टिकाऊ खेती पद्धतियों पर केंद्रित है, जो एमआईडीएच के उद्देश्यों के अनुरूप है।

अब तक लगभग 160 प्रतिभागियों ने विभिन्न जिलों में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। किसानों और ग्रामीण युवाओं से इस पहल को बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से स्थानीय क्षमता का निर्माण हो रहा है, रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं और प्रतिभागी आधुनिक बागवानी तकनीकों से परिचित हो रहे हैं।

सीईएचएसआई (CEHSI) इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के बागवानी क्षेत्र में कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कृषि प्रणाली अधिक उत्पादक, टिकाऊ और सशक्त बन सके।

CEHSI द्वारा हिमाचल प्रदेश की महिला किसानों के लिए 5-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण और एक्सपोज़र या

हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI), बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश के सहयोग से और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश की 31 महिला किसानों के लिए करनाल, हरियाणा में 5-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण और एक्सपोज़र यात्रा आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और इसमें प्रतिभागियों को कक्षा आधारित सत्रों और फील्ड डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से व्यावहारिक कौशल और तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है।

प्रशिक्षण में मुख्य विषय हैं फसल कटाई के बाद नुकसान प्रबंधन, अच्छी कृषि प्रथाएँ (GAPs) और क्लस्टर आधारित खेती। कक्षा सत्रों में गुणवत्ता प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला के बारे में जानकारी दी जा रही है, जबकि फील्ड डेमोंस्ट्रेशन से किसान इन तकनीकों को सीधे अपने खेतों में लागू करना सीख रहे हैं।

कार्यक्रम के एक्सपोज़र भाग के तहत प्रतिभागी हरियाणा के प्रमुख बागवानी संस्थानों का दौरा कर रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड बीकीपिंग डेवलपमेंट सेंटर (IBDC), रामनगर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स (CEV), घरौंडा, सेंटर फॉर सबट्रॉपिकल फ्रूट्स (CSTF), लदवा, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी (MHU) और हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (HTI)। इन दौरों में आधुनिक खेती तकनीकें, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, कीट एवं परागक प्रबंधन और सफल क्लस्टर आधारित खेती के मॉडल दिखाए जा रहे हैं।

कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच आपसी सीख, आत्मविश्वास और विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद को बढ़ावा देता है, जिससे वे अपने गाँवों की स्थानीय चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान सीख सकें। शुरुआती प्रतिक्रिया में महिला किसान बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने अपने गाँवों में सीखी गई तकनीकों को अपनाने की योजना बनाई है।

आवासीय प्रशिक्षण और एक्सपोज़र यात्रा के माध्यम से, CEHSI का उद्देश्य महिला किसानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और बागवानी क्षेत्र में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह पहल CEHSI की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि महिला किसान अधिक उत्पादक, सक्षम और टिकाऊ बागवानी भविष्य के लिए परिवर्तनकर्ता बन सकें।

CEFMI – आगामी कार्यक्रम

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ़ार्म मैकेनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI) आपको एक **वन-डे राउंडटेबल** में आमंत्रित करता है, जिसका विषय है: **"क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर के लिए मैकेनाइजेशन"** यह कार्यक्रम CSR लीडर्स, एग्री-इनोवेटर्स और डेवलपमेंट पार्टनर्स को एक साथ लाएगा, ताकि टिकाऊ और प्रभावी कृषि मशीनीकरण समाधानों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

10 नवम्बर 2025
सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक
मैग्नोलिया हॉल, इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली

आइए, मिलकर भारतीय कृषि के लिए एक क्लाइमेट-स्मार्ट भविष्य का निर्माण करें!
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पंजीकरण करें: https://forms.gle/YtsQFUxEmxogo7Gq7

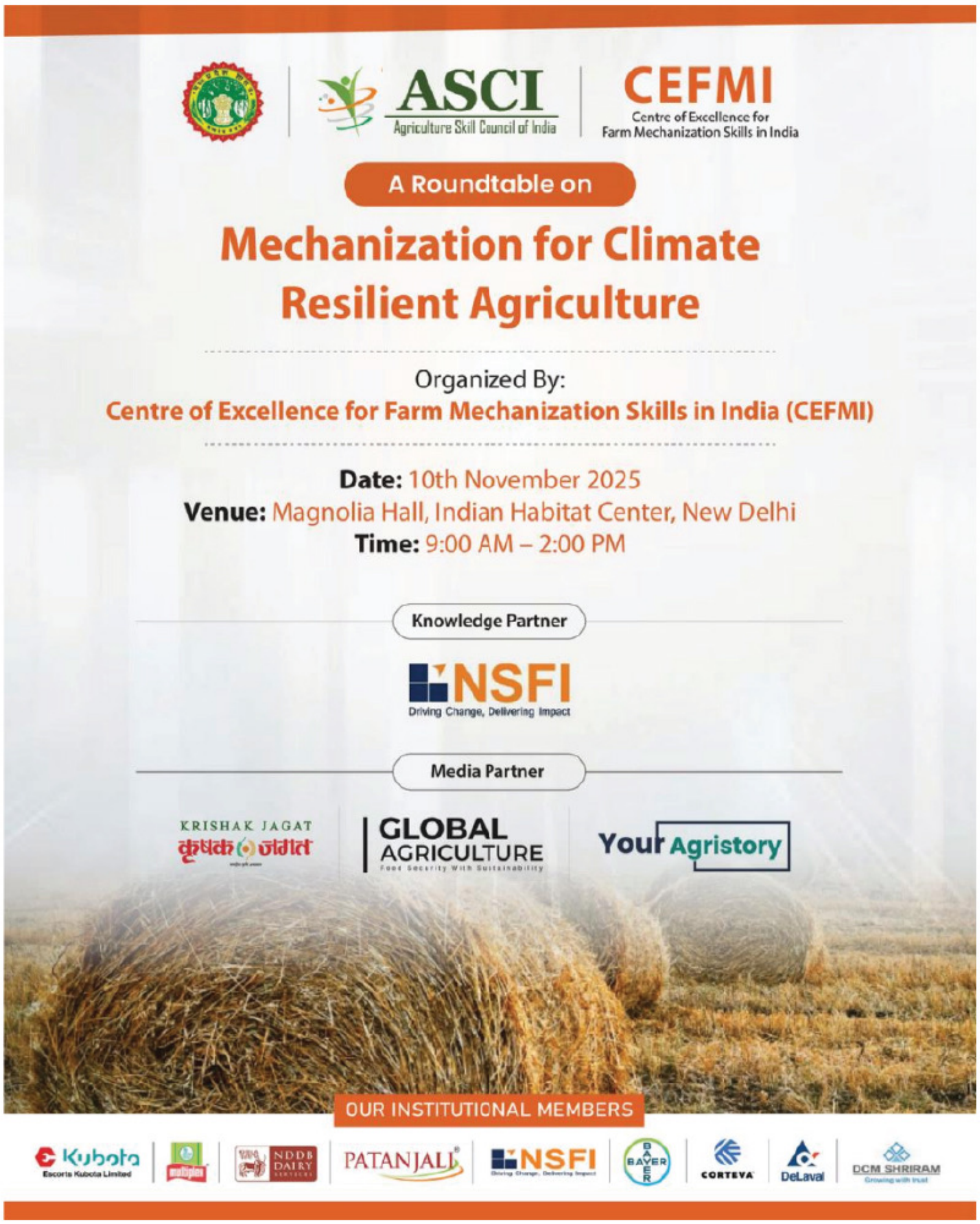

SCAN TO REGISTER

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india